



**REVIEW OF PERFORMANCE OF THE
CENTRE FOR RAILWAY INFORMATION SYSTEMS (CRIS) BY THE
MINISTRY OF RAILWAYS FOR THE YEAR 2017-18.**

The Centre for Railway Information System (CRIS) was constituted by the Ministry of Railways on 01.07.1986 as an autonomous body for computerisation activities on Indian Railways. Over the years, CRIS has taken up projects pertaining to all aspects of Railway working.

In the year 2017-18, thrust was given to developing features for improving passenger experience, providing better information to freight customers, integrating Indian Railway's Financial System, and increasing transparency in procurement. In addition, there was an immediate requirement to implement GST (Goods and Services Tax) related functionalities for Indian Railways within tight timelines.

In order to improve passenger experience, provision was made in the Unreserved Ticketing System (UTS) Android App to book Paperless Mobile ticket using QR (Quick Response) code placed at source station for suburban commuters in Mumbai. Provisions were made in PRS (Passenger Reservation system) to send SMS to passengers of Rajdhani, Shatabdi, Tejas, Gatimaan, Duronto, Jan Shatabdi, Suvidha and GaribRath Trains if the train is delayed for 60 minutes or more. On an average, approximately 2.5 lakh SMS alerts were sent on a daily basis.

For providing better information to freight customers, Long Term Tariff Contract (LTTTC) in Freight Operations was inaugurated. A mobile app for Indian Railway (IR) freight customers was designed to bring ease of doing business for individuals and corporate. This app provides enhanced GIS {geographic(al) information system} views, dashboard and data views on multiple freight related aspects such as Track and Trace of Consignments, Private Freight Terminal/Container Rail Terminal Locations over IR, Loading/Unloading Terminals, Terminal-wise pending/fulfilled indents, Freight Rates, Route Information, along with expected freight to be charged by Railways for any movement of consignment through the Freight Calculator option.

For making train operations more efficient, SFOORTI - an innovative Mobile App developed for Freight Managers which provides features for monitoring and managing freight business using GIS views and Dashboard was launched. Train Punctuality Dashboard and IS Reports were developed and implemented in Android & iOS Mobile App.

For integrating IR's financial system and implementing GST, the I-PAS (Integrated Payroll Accounting System) application was rolled out across Indian Railways. GST was implemented successfully on target in all Indian Railway applications. For manual recoveries, CRIS developed a utility for capturing required data and made it available to all Zonal Railways. The calculation logic of GST amount was changed in UTS, PPS and Freight Operations Information System (FOIS) to match the latest instructions. A number of changes had to be made in the critical I-PAS, PRS, UTS and FOIS application, in addition to all other revenue/expenditure based applications. All the code changes were made, testing completed and training of Railway Staff carried out within the deadline.

851373/2021/CIS DTE

INFORMATION
CONFIDENTIAL

(Part 10 of 10)
Page 10 of 10
CONFIDENTIAL

In order to improve efficiency and transparency in procurement, E-procurement system was redesigned to migrate it from its obsolete software platform to standard Java EE. The NIT bidding module of the redesigned application was launched. Publication of all Integrated Material Management System(IMMS) tenders through new software started. Online tender decision module was launched in September 2017. In IMMS, vendors started applying online for modification advice against Purchase Order (PO) placed against them, since POs are being sent to them online. CRIS was awarded for outstanding contribution in bringing transparency in Railway tendering and contractual matters through IT initiatives during the Vigilance Week celebrations.

The accounts of CRIS for the year 2017-18 have been audited by the office of Comptroller and Auditor General.



वर्ष 2017-18 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) के निष्पादन की समीक्षा।

भारतीय रेल में कंप्यूटरीकरण संबंधी कार्यों के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में 01.07.1986 को रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) का गठन किया गया था। विगत वर्षों में, क्रिस ने रेलवे के सभी पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

2017-18 में, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने, माल यातायात ग्राहकों को बेहतर जानकारी प्रदान करने, भारतीय रेल की वित्तीय प्रणाली को एकीकृत करने और खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया था। इसके अलावा, कम समय-सीमा के भीतर भारतीय रेल के लिए जीएसटी (माल और सेवा कर) संबंधित व्यावहारिकताओं को लागू करने की तत्काल आवश्यकता थी।

यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, मुंबई में उपनगरीय यात्रियों के लिए प्रस्थान स्टेशन पर स्थापित क्यूआर (क्विक रिस्पॉन्स) कोड का उपयोग करके कागजरहित मोबाइल टिकट बुक करने के लिए अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) एंड्रॉइड ऐप में प्रारंभ किया गया था। यदि गाड़ी के चलने में 60 मिनट या इससे अधिक का विलंब होता है, तो राजधानी, शताब्दी, तेजस, गतिमान, दुरंतो, जन शताब्दी, सुविधा और गरीबरथ गाड़ियों के यात्रियों को एसएमएस भेजने के लिए पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) में प्रबंधन किए गए थे। ऑसतन, दैनिक आधार पर लगभग 2.5 लाख एसएमएस अलर्ट भेजे गए थे।

माल यातायात ग्राहकों को बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए, माल टुलाई परिचालन में लॉन्ग टर्म टैरिफ कॅन्ट्रैक्ट (एलटीटीसी) का शुभारंभ किया गया। व्यक्तियों और कंपनियों के लिए व्यापार में सुगमता लाने के लिए भारतीय रेल (भारे) के माल यातायात ग्राहकों के लिए एक मोबाइल ऐप डिजाइन किया गया था। यह ऐप फ्रंट क्लैम्बुलेटर विकल्प के माध्यम से परेषण की किसी भी गतिविधि के लिए रेलों द्वारा वसूले जाने वाले अपेक्षित मालभाई के साथ-साथ परेषणों की पड़ताल, भारतीय रेल में निजी माल टुलाई टर्मिनलों/कंटेनर रेल टर्मिनलों, लदान/उतराई टर्मिनलों, टर्मिनल-वार लंबित/अपूरित मंगपत्रों, माल टुलाई दरों, मार्ग की जानकारी जैसे अनेक माल टुलाई संबंधी पहलुओं पर संवर्धित जीआईएस (शैंगलिक सूचना प्रणाली) दृष्टिकोण, डैशबोर्ड और आंकड़े संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

गाड़ी परिचालन को और अधिक दक्ष बनाने के लिए, माल यातायात प्रबंधकों के लिए विकसित किए गए स्फूर्ति नामक एक अभिनव मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया जो है जो जीआईएस दृष्टिकोणों और डैशबोर्ड का उपयोग करके माल टुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है। गाड़ी समयपालन डैशबोर्ड और आईएस रिपोर्ट्स को एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल ऐप में विकसित और कार्यान्वित किया गया।

भारतीय रेल में वित्तीय प्रणाली को एकीकृत करने और जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए, भारतीय रेल में आई-पीएस (एकीकृत वेतन लेखा प्रणाली) अनुप्रयोग को लागू किया गया था। भारतीय रेल के सभी अनुप्रयोगों में जीएसटी का सफलतापूर्वक लक्ष्य-आधारित कार्यान्वयन किया गया था। कर्मचारियों द्वारा वसूली के लिए, क्रिस ने अपेक्षित आंकड़ों को दर्ज करने के लिए एक तंत्र विकसित किया और इसे सभी क्षेत्रीय रेलों को उपलब्ध कराया गया। नवीनतम अनुदेशों का पालन करने के लिए यूटीएस, पीआरएस और माल यातायात परिचालन प्रणाली (एफओआईएस) में जीएसटी राशि की गणना की विधि को बदल दिया गया था। अन्य सभी राजस्व / व्यय आधारित अनुप्रयोगों के अलावा, महत्वपूर्ण आई-पीएस, पीआरएस, यूटीएस और एफओआईएस अनुप्रयोग में कई बदलाव करने पड़े। समय सीमा के भीतर सभी कोड परिदृष्टित किए गए, परीक्षण पूरे किए गए और रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।


निम्नलिखित कार्य
आवश्यक है कि
आवश्यक है कि
आवश्यक है कि
आवश्यक है कि

खरीद में दक्षता और पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए, ई-खरीद प्रणाली को इसके पुराने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से मानक जावा ईई में परिवर्तित करने के लिए पुनः डिजाइन किया गया था। पुनः डिजाइन किए गए अनुप्रयोग का एनआईटी बिल्डिंग मॉड्यूल शुरू किया गया था। संचालित नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी एकीकृत सामग्री प्रबंधन प्रणाली (आईएमएमएस) निविदाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। ऑनलाइन निविदा निर्णय मॉड्यूल सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। आईएमएमएस में, विक्रेताओं ने उनको दिए गए क्रय आदेश (पीओ) में आशोधन की सूचना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें क्रय आदेश ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। सतर्कता सप्ताह समारोह के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलकदमियों के माध्यम से रेलवे के निविदा और अनुबंध संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्रिस को सम्मानित किया गया था।

वर्ष 2017-18 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा क्रिस के खातों की लेखा परीक्षा की गई है।



अनुमोदित
AUTHENTICATED


 (Sulabhan C. Anand)
 Minister of State in the
 Ministry of Railways

Statement giving reasons for delay in laying of Annual Report and Audited Accounts for the Centre for Railway Information Systems for the year 2017-18

The Annual Report and the Receipts and Payments Accounts of CRIS for the year 2017-18 were closed and made available to the Principal Director of Audit, Northern Railway on 28.05.2018. Audit of Accounts commenced on 06.06.2018 and completed on 27.07.2018. Draft Audit Reports were issued to CRIS on 13.09.2018 and 27.09.2018. Replies were sent to Audit on 01.10.2018 & 12.10.2018. The Audit Certificate dated 28.12.2018 was received on 28.12.2018. The Audited Accounts along with the Annual Report for the year 2017-18 was approved by the Executive Committee through circulation of papers on 11.01.2019 and by the Governing Council of CRIS through circulation of papers on 04.02.2019. Accordingly, the Annual Report and Audited Accounts for the year 2017-18 is being placed on the Table of both the Houses of Parliament during the ensuing Session.

851373/2021/CIS DTE

अधिकृत
AUTHENTICATED

(श्रीमान श्री. अशोक)
(SHRI. A. ASHOK)
उत्तर रेलवे के मुख्य अधिकारी
Minister of State in the
Ministry of Railways

वर्ष 2017-18 के लिए रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को तैयार करने में देरी के संबंध में विवरण

वर्ष 2017-18 के लिए क्रिस की वार्षिक रिपोर्ट और प्राप्तियां और भुगतान खाते बंद कर दिए गए और 28.05.2018 को लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, उत्तर रेलवे को उपलब्ध कराए गए। खातों की लेखा परीक्षा 06.06.2018 को शुरू हुई और 27.07.2018 को पूरी हुई। 13.09.2018 और 27.09.2018 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट्स के प्रारूप क्रिस को जारी किए गए। 01.10.2018 और 12.10.2018 को लेखा परीक्षा को उत्तर भेजे गए थे। दिनांक 28.12.2018 का लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र 28.12.2018 को प्राप्त हुआ। वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखा परीक्षित खातों को कार्यकारी समिति द्वारा 11.01.2019 को कागजात के परिपत्रण के माध्यम से और क्रिस की नियंत्रक परिषद् द्वारा 04.02.2019 को कागजात के परिपत्रण के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को आगामी सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे जा रहे हैं।